रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2018/वैशाख 22, 1940
No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2018/VAISAKHA 22, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन ।

सं. 12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीवाई.— जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरणों को प्रोत्साहन देकर तथा भीम-यूपीआई प्लेटफार्मों के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों के बीच भीम-यूपीआई के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए "भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक" नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017 –डीपीडी के जरिए योजना के प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया है ।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है ।

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"विषय: <u>व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) प्रोत्साहन योजना</u>"

1. पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात:-

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM Cashback Scheme for Merchants

No. 12/13/2017–DPD-MeitY..—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants', with the objective to promote usage of BHIM-UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM-UPI platform.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants':-

Subject: "BHIM (Bharat Interface for Money) incentive scheme for Merchants"

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

BHIM incentive scheme for Merchants

1.1 Paragraph 2.1: The scope of the scheme shall be limited to BHIM App users who have declared themselves as "I am a merchant" and have MCC "0000" and Merchants on-boarded by any bank receiving payment through BHIM-UPI and have MCC other than "0000". The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.2 Paragraph 2.3: The incentive slabs for merchants are:

a) **BHIM Merchant :** BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" will be eligible for following incentive:

No. of credit transactions (per month)	*Incentive to the merchant (at the end of the month)*	*Conditions*
Minimum credit transactions to be done to start earning the incentive =>10	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for calculation of "month"

a) **BHIM-UPI merchants :** Merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than "0000"

No. of credit transactions (per month)	*Incentive to the merchant (at the end of the month)*	*Conditions*
Minimum transactions to be done to start earning the incentive =>5	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for

भीम कैशबैक योजना" को भीम एप्प पर नवीन प्रयोक्ताओं की ऑनबोर्डिंग को प्रोत्साहित करने तथा भीम-यूपीआई आधारित लेनदेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

भीम एप्प के डाउनलोड, इंस्टॉलिंग, भीम एप्प को अपने बैंक खातों के साथ लिंक करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना और पहला वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक करना।

भीम-यूपीआई के प्रयोग द्वारा लेनदेन की संख्या में बढ़ोत्तरी करना।

व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना

1.2 पैराग्राफ : 2.1 - इस योजना में दो घटक हैं क) भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन और ख) भीम-यूपीआई पर लेनदेन के लिए प्रोत्साहन। घटक 'क' के कार्यक्षेत्र में केवल भीम एप्प प्रयोक्ता ही आते हैं और घटक 'ख' के कार्यक्षेत्र में भीम एप्प के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प भी आते हैं। इस योजना की अवधि 12 महीने यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक है तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ 2.3 – "ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन" का भुगतान भीम एप्प के ऐसे नवीन प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो अपने भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे अपने बैंक के खाते/खातों के साथ जोड़ेंगे तथा भीम एप्प के जरिए सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन करेंगे। "लेनदेन पर प्रोत्साहनों" का भुगतान ऐसे प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करते हैं।

1.4 पैराग्राफ : 2.4 – प्रोत्साहन निम्नलिखित के अनुसार दिए जाएंगे :

तालिक-I

भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन

क्र.सं.	ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन	**प्रति भीम एप्प प्रयोक्ता कुल राशि (रु.में)**
1.	नये भीम एप्प को प्रयोक्ता द्वारा डाउनलोड, इंस्टॉल किए जाने और सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन पूर्ण किए जाने पर	51

तालिक-II

भीम एप्प पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन

क्र.सं.	लेनदेनों पर प्रोत्साहन	राशि (रु. में)		शर्तें
1.	विशिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए भीम और बैकों भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	25 प्रति लेनदेन		न्यूनतम लेनदेन मूल्य 100 रु. होना चाहिए। प्रति कलेंडर माह अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। केवल विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन केलिए पात्र होंगे।
2.	भीम और वित्तीय लेनदेन के लिए बैंको के भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	**प्रति माह लेनदेनों की संख्या**	**प्रति माह प्रोत्साहन (रु.)**	न्यूनतम लेनदन मूल्य 10 रु. होना चाहिए। "माह" की गणना के लिए कलेंडर माह का प्रयोग किया जाएगा।
		>= 25 पर 50 से कम	100	
		>= 50 पर 100 से कम	200	
		> 100	250	

1.1 Paragraph 1.4: In the promotion of digital payments, incentive schemes are widely used to promote adoption of the new technologies, platforms and apps that are launched in the market and it has proved effective. The **"BHIM cashback scheme for individuals"** has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the usage of BHIM-UPI based transactions. The objectives of the scheme are:

- Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and making first successful financial transaction.
- Increase in the number of transactions using BHIM-UPI

BHIM cashback scheme for Individuals

1.2 Paragraph: 2.1 The scheme has two components a) Incentive for onboarding over BHIM App and b) Incentive on transactions over BHIM-UPI. The scope of the component 'a' is only BHIM app users and the scope of the component 'b' is the users of BHIM app as well as BHIM-UPI apps of the banks. The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.3 Paragraph: 2.3 The "incentive for onboarding" will be paid to the new users of the BHIM app who successfully download the BHIM app, link the BHIM app with their bank account/s and undertake one successful financial transaction through BHIM app. The "incentive on transactions" will be paid to the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks.

1.4 Paragraph: 2.4 The incentives will be paid as per the following:

TABLE-I

Incentive for onboarding on BHIM app

[illegible]	[illegible]ling	**Total amount (in Rs.) per BHIM app user**
1	New BHIM app user on downloading , installing and successfully completing one financial transaction	51

TABLE-II

Incentive on transactions over BHIM-UPI

S. No.	**Incentive on transactions**	**Amount (in Rs.)**		**Conditions**
1	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for unique financial transaction.	25 per transaction		Minimum transaction value should be Rs 100. The incentive will be paid for maximum 20 unique transactions per calender month. Only unique transactions will be eligible for incentive.
2	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for financial transaction.	**Number of transactions per month**	**Incentive per month (Rs.)**	Minimum transaction value should be Rs 10. Calendar month will be used for calculation of "month"
		>=25 but less than 50	100	
		>=50 but less than 100	200	
		>=100	250	

1.5 Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives:

a) For "incentive for onboarding on BHIM app", the user has to download, install and link BHIM app with the bank account/s and successfully complete one financial transaction of any value. The incentive will paid

1.1 पैराग्राफ 2.1 भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना 31 मार्च, 2019 तक प्रचालन में रहेगी।

1.2 पैराग्राफ : 2.3 –

- आधार प्रमाणन के बारे में उपकरण को कोई भान (जानकारी) नहीं होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से उपकरण यानि माइक्रो-एटीएम/पीओएस, एमपीओएस, कियोस्क/टेबलेट/मोबाइल हैंडसेट इत्यादि को शामिल किया गया है, परन्तु व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए लेनदेन हो और भुगतान आधार संख्या और बॉयोमीट्रिक प्रमाणन द्वारा किया जाए। तथापि, माइक्रो एटीएम के जिरए व्यापारिक पत्र व्यवहार (बीसी) के जरिए नियमित रूप से किए जाने वाले बैकिंग संबंधी लेनदेन को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भीम आधार लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन 2 रुपए की न्यूनतम प्रोत्साहन और 50 रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन के साथ 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि के लेनदेन मूल्य पर 5% की दर से प्रोत्साहन दिया जाए।
- लेनदेन मूल्य के 0.5% का संपूर्ण प्रोत्साहन अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी को दिया जाना है तथा किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा अपनी बैकिंग/प्रचालन संबंधी लागत को चुकाने के लिए प्रोत्साहन का कोई भी अंश नहीं रखा जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ : 3.1 –

ख) प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र न्यूनतम और अधिकतम लेनदेन मूल्य क्रमशः 25 रु. और 10,000 रु. है।

1.4 पैराग्राफ : 3.2 –

(ii) भीम आधार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य व्यापारी की प्रचालन संबंधी लागत को चुकाना तथा भीम आधार आधारित डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

2. अनुबंध 1-

क) "वैध वित्तीय लेनदेन - 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि का लेनदेन"।

3. अन्य शर्तें व निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Extension and modification in the BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive Scheme

No. 12/9/2017–DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive, with the aim to incentivize adoption of BHIM Aadhaar merchants and promote digital payments across un-organized sector as well as the citizens using BHIM Aadhaar.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive scheme:-

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are subsituted namely:-

1.1 Paragraph 2.1- The BHIM Aadhaar Merchant Incentive Scheme will be operational till 31st March 2019.

1.2 Paragraph 2.3 –

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939
No. 05]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

विषय : 2000 रु. या इससे कम मूल्य के डेबिट कार्ड /भीम यूपीआई/एईपीएस लेनदेनों पी एमडीआर प्रभार में छूट प्रदान करना।

सं. 6(19)/2017-डीपीडी-1:—

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल शासन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवा कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान इको सिस्टम का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने तथा उन सभी लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का समावेशन करने की क्षमता है जो बचे रह गए हैं।

2. 1 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ के डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लक्ष्य की उद्घोषणा की थी।

3. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में, व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां लगभग 90% व्यापारी किराने की छोटी दुकानों, स्थानीय आउटलेट इत्यादि के रूप में असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रेता, ऑटो/टैक्सी ड्राइवर इत्यादि हैं, जो असंगठित व्यापारियों का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से प्रत्येक व्यापारी की लेनदेन राशि आमतौर पर छोटी होती है।

4. जब डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोसिस्टम में कोई भुगतान पीओएस मशीन या क्यूआर "स्कैन और भुगतान" या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से व्यापारी बिक्री बिन्दु (पीओएस) पर किया जाता है तो व्यापारिक छूट दर (एमडीआर), व्यापारी द्वारा उसके बैंक (अधिग्रहणकर्ता) को देय होती है।

xii. सलाहकार प्रक्रिया जिसमें आरबीआई, आईबीए और बैंक शामिल हैं के माध्यम से ऐसे कम मूल्य वाले लेनदेनों के संबंध में प्रतिपूर्ति तंत्र तैयार किया जाएगा । इसके बाद तिमाही आधार पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति हेतु अधिग्राहक बैंकों के लिए प्रक्रिया तैयार की जाएगी तथा इसके विषय में संबंधित सभी को जानकारी दी जाएगी।

7. बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2018 से कम मूल्य के लेनदेनों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति की इस नई योजना में परिवर्तन निर्विघ्न रूप से किया जाए।

गोपालकृष्णन एस. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or equal to Rs. 2000/-.

No. 6(19)/2017-DPD-1.—

1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy and extend inclusion of financial services to all those who remain excluded.

2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore digital payment transactions for FY. 2017-18.

3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores, local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.

4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR "scan & pay" or online mode of payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network operator.

5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have been proposed for transactions.

6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted. The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-

   i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from 1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.

   ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/-. However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of Rs.1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire transaction value of Rs. 2300/-.